VOL- IX | ISSUE- XI | NOVEMBER | 2022 | PEER REVIEW e-JOURNAL | IMPACT FACTOR 7.331 | ISSN 2349-638x

नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियाँ

श्रीमती वीणा
विभागाध्यक्ष एवं सह आचार्य रसायनशास्त्र
श्रीमती नर्बदा देवी बिहानी
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नोहर

सारांश

नई शिक्षा नीति २०२० का मुख्य लक्ष्य भारत देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूर्ण करना है। नई शिक्षा नीति हमारे देश की प्राचीनता को एक परंपरा के रूप में कायम रखते हुए सांस्कृतिक मूल्यों को विस्तारितता का रूप देने में विश्वास रखती है। इस शिक्षा नीति का एक स्वरूप देखने को मिलता है वह स्वरूप है इस नई शिक्षा नीति का सिद्धांत पर आधारित होना। मगर इस नीति को अगर क्रियान्वयन में लिया जाए तो कुछ चुनौतियाँ भी सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। शिक्षा नीति को लागू करने से पहले हमें उन चुनौतियों को शांत करना होगा जो एक रुकावट के रूप में खड़ी नजर आ रही है। जैसे शिक्षण संस्थाओं की स्वायत्तता को हर कीमत पर कायम किया जाए, केवल कागजी खानापूर्ति की बजाय नई शिक्षा नीति २०२० को लागू करने की गंभीर कोशिश की जाए आदि–आदि। मुख्य शब्द : क्रियान्वयन, चुनौतियाँ, स्वायत्तता, खानापूर्ति।

प्रस्तावना

नई शिक्षा नीति २०२० के माध्यम से शैक्षिक ढांचे को बेहतर बनाने का भारत सरकार द्वारा किया जा रहा प्रयास वास्तविक रूप में एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। प्राचीन भारतीय ज्ञान भंडार को ध्यान में रखते हुए इस नीति को तैयार किया गया है। जैसे प्राचीन भारत का इतिहास इस तथ्य को जगत के सामने प्रकट करता है कि भारत वर्ष में शिक्षा का लक्ष्य सांसारिक जीवन या विद्यालय के बाद के जीवन के तैयारी के रूप में ज्ञान अर्जन नहीं बल्कि पूर्ण आत्मज्ञान तथा मुक्ति के रूप को एक आकार प्रदान करना था तभी तो हमारे भारतवर्ष में तक्षशिला, नालंदा व वल्लभी तथा विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। जहां पर विद्यार्थी अपने अध्ययन के विविध क्षेत्र में शिक्षण शोध संबंधी उच्च सोपान को प्राप्त कर सकें। वर्तमान स्वरूप की इस शिक्षा नीति में उपरोक्त बातों को ध्यान में रखा गया है।[२] इस नीति के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाई गई है। इस नीति में उन समुदायों पर विशेष ध्यान देने का कार्य भी किया गया है जो शिक्षा से अपने को दूर रखते हुए नजर आते हैं क्योंकि शिक्षा बराबरी सुनिश्चित करने का एक बड़ा मंच है।

अध्ययन के उद्देश्य

- नई शिक्षा नीति २०२० के स्वरूप को जानने हेतु।
- प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था और नई शिक्षा नीति २०२० के तुलनात्मक अध्ययन हेतु।
- भारतीय सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति २०२० को लागू करने में किए गए

परिवर्तन के सराहनीय कार्य को जानने हेतु।

- ❖ इस शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में आने वाले चुनौतियां और उनके उपायों को जानने हेतु उपयोगी।

शैक्षिक प्रणाली कैसी भी क्यों न हो उसका उद्देश्य हमेशा अच्छे मानव समुदायों का विकास करना ही होता है। यहां मानव समुदायों का अर्थ किसी जाति विशेष या धर्म विशेष लेने से न होकर केवल उस मानव समुदाय से है जो हर कार्य को तर्क की कसौटी पर परखे, जो एक अच्छी शैक्षिक प्रणाली से ही संभव होता नजर आता है। ऐसी ही शैक्षिक प्रणाली नई शिक्षा नीति २०२० है। इस शिक्षा नीति के तहत हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं को स्वीकृति प्रदान की गई है ताकि बच्चे का पूर्ण विकास हो सके। इस नीति में शिक्षक और अभिभावक को भी मुख्य स्थान दिया गया है ताकि ये दोनों बच्चे की क्षमता के अनुरूप उसे संवेदनशीलता प्रदान करें और उसके अकादमिक क्षमता, सर्वांगीण विकास पर पूरा ध्यान दे पाएं। इस शिक्षा नीति में बुनियादी साक्षरता व संख्याज्ञान को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है जिससे बच्चा प्राथमिक कक्षा में सीखने के मूलभूत कौशलों को प्राप्त कर सके। इस शिक्षा नीति का एक अन्य रूप भी है वह है इसका लचीलापन ताकि विद्यार्थियों में उनके सीखने के तौर तरीके तथा कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता उनमें पैदा की जा सके। भारतीय कला और विज्ञान के बीच, पाठ्यक्रम तथा पाठ्येत्तर गतिविधि के बीच, व्यवसायिक व शैक्षणिक धाराओं के बीच कोई स्पष्ट अलगाव न पैदा हो जिससे ज्ञान क्षेत्रों के मध्य कोई हानिकारक ऊंच–नीच तथा परस्पर दूरी एवं असम्बद्धता को दूर किया जा सके। यह सारी बातें इस शिक्षा नीति में दृष्टिगोचर होती हैं। इन सब बातों के अलावा भी बहुत सारे शीर्षक बिंदु हैं जो इस शिक्षा नीति को वर्तमान के लिए उपयोगी सिद्ध करते हैं। जैसे : सभी ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए उपयोगी, अवधारणात्मक समझ को विकसित करने के लिए उत्तम, रचनात्मक और आर्थिक सोच के लिए सहज, मानवीय तथा संवैधानिक मूल्यों के महत्व को जानने के लिए आवश्यक, जीवन कौशल के लिए उपयोगी, तकनीकी ज्ञान में उपयोगी, शिक्षकों और संकाय को सीखने के लिए एक प्रक्रिया का केंद्र तथा प्राचीन भारतीय गौरव को बनाए रखने में उपयोगी।

इतनी बहु उपयोगी शिक्षा नीति होने के बाद भी इसे क्रियान्वयन करने में सरकार को अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।[३]

चुनौतियाँ

- ➢ हमारे भारत देश में लगभग एक तिहाई बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने से पहले ही विद्यालय छोड़ देते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि अधिकांश बच्चे जो विद्यालय जाने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं वे सभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या फिर धार्मिक अल्पसंख्यकों, दिव्यांग समूह से संबंधित होते हैं।
- ➢ बुनियादी ढांचे की कमी भी एक चुनौती का कारण है यह अक्सर देखा जाता है कि विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में बिजली, पानी, शौचालय, चारदीवारी, पुस्तकालय, कंप्यूटर आदि का अभाव है। जिसका परिणाम होता है शिक्षा प्रणाली का प्रभावित होना।

- शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के विफल होने का खतरा भी है। इसका मुख्य कारण शिक्षा नीति में बदलाव करते समय रोडमैप का पालन नहीं करना और शिक्षा की नीतियों को तैयार करते वक्त सभी के हित को ध्यान में रखना है।
- ौम्त के अनुसार जो कि एक गैर सरकारी संगठन है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, पूरे भारत में ग्रामीण और शहरी मलिन बस्तियों में बच्चों के साथ काम करता है। भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में इस के बुनियादी ढांचे में निवेश किया हो ऐसा हो सकता है, मगर यह आशा के अनुरूप सफल नहीं दिखाई देता।
- नई शिक्षा नीति २०२० के सामने एक चुनौती शिक्षकों की कमी को दूर करना भी है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट (२०१७) के अनुसार एकल शिक्षक के भरोसे बड़ी संख्या में विद्यालयों का संचालन हो रहा है जो कि शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। वर्तमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कुल स्वीकृत शिक्षण पदों में से प्रोफेसर के ३५ प्रतिशत, एसोसिएट प्रोफेसर के ४६ प्रतिशत और सहायक प्रोफेसर के २६ प्रतिशत पद भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में रिक्त हैं।
- महाविद्यालयों या फिर विश्वविद्यालय में रिक्त पद जब तक रहेंगे तब तक विद्यार्थियों के अध्ययन कार्य व विश्वविद्यालयों के उच्च शोध संस्थानों से सुखद परिणाम निकल कर नहीं आ सकेंगे।[४] अत: भारत सरकार को उच्च शिक्षा प्राप्त वर्ग को एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर के आधार पर महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में नियुक्ति देनी चाहिए। उदाहरण के लिए राजस्थान सरकार द्वारा महाविद्यालयों में विद्या संबल योजना आदि।[५]
- नई शिक्षा नीति के समक्ष एक महत्वपूर्ण चुनौती विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रोफेसरों की जवाबदेही और प्रदर्शन सुनिश्चित करने से संबंधित सूत्र को लागू करना भी है। आज संसार के कई विश्वविद्यालयों में अपने साथियों और छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर शिक्षकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है।
- शिक्षा नीति के मसौदे में त्रिभाषा नीति भी नई शिक्षा नीति २०२० के सामने एक चुनौती प्रस्तुत कर रही है, जिसमें गैर हिन्दी भाषा क्षेत्रों में मातृभाषा और अंग्रेजी भाषा के अलावा हिन्दी को तीसरी भाषा बनाने की सिफारिश की गई है। तीन भाषा सूत्र नया नहीं है तथा पिछली शिक्षा नीतियों में इसकी पहले से ही सिफारिश की गई थी।[६]

नई शिक्षा नीति २०२० भारतीय सरकार द्वारा शिक्षा प्रणाली में एक बड़े बदलाव का संकेत देता है लेकिन चुनौतियां भी देखी जा रही हैं। उल्लेखनीय है कि इन चुनौतियों से निपटने का प्रयास किया जाएगा। किसी भी नीति की प्रभावशीलता उसके क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। ऐसे वातावरण में क्रियान्वयन के लिए कई निकायों द्वारा समन्वित और व्यवस्थित तरीके से बहुत सी समस्याओं के हल करने की पहल भारतीय सरकार को करनी होगी जिसमें नई शिक्षा

नीति के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियाँ भी एक समस्या है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

१. राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० (डभ्त्क) भारत सरकार, पृ० सं० ४
२. वही पृ० सं० ४
३. राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० एक सिंहावलोकन, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र) पृ० सं० ११—३५
४. नई शिक्षा नीति २०२० चुनौतियाँ इन्टरनेट से प्राप्त।
५. लेखिका, श्रीमती नर्बदा देवी बिहानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नोहर, रसायन शास्त्र विभागाध्यक्ष के निजी विचार।
६. नई शिक्षा नीति २०२० चुनौतियाँ इन्टरनेट से प्राप्त।

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal
ISSN 2349-638X
www aiirjournal.com